गुजरात में विद्युत, तेल और प्राकृतिक गैस के संयंत्रों की स्थापना

2651. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र सहित गुजरात में विद्युत, तेल और प्राकृतिक गैस के संयंत्र स्थापित किए जाने के मामले में जिला-वार कितने-कितने प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अभी भी लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इनके लम्बित पड़े रहने के मुख्य कारण क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) बड़ौदा तथा सूरत जिलों में दो विद्युत परियोजनाएं और मेहसाना जिले में तेल प्राकृतिक गैस की दो परियोजनाएं स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। [illegible] भावनगर और अमरेली में स्थापित [illegible] प्रस्तावित चार विद्युत परियोजनाओं को नामंजूर किया गया था।

(ख) और (ग) आज की स्थिति के अनुसार पांच विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं। तेल और प्राकृतिक गैस की कोई परियोजना लंबित नहीं हैं। लंबित रहने का मुख्य कारण परियोजना प्रस्तावों के साथ-साथ अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े प्रस्तुत न किया जाना है।

Production of Fruits and Vegetables

2652. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the production of fruit and vegetables in the country is not enough to fully meet the indigenous and export requirements;

(b) whether the export of these items has been adversely affected as a result thereof;

(c) if so, the details of fruits and vegetables growth in comparison to other developing countries; and

(d) the reasons for the shortfall and the steps taken or proposed to be taken to adequately augment the indigenous production of fruits and vegetables?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Reasons of shortfall for production of fruits and vegetables are as follows:-

(i) Low productivity.

(ii) Non-availability of adequate seeds and planting material of improved varieties.

(iii) Weak infrastructure for post-harvest handling and marketing.

(iv) Weak extension support.

Government of India during 8th Plan has launched the following schemes to augment the indigenous production of [illegible] vegetables and improving the post-harvest handling.

	Name of the Scheme	8th plan outlay (Rs. in crore)
(A)	*Schemes of the division*	
1.	Integrated development of fruits	74.40
2.	Development of vegetables	15.00
3.	Development of mushroom	15.68
4.	Use of Plastics in Agriculture	250.00
5.	Development of root and tuber crops	2.50
(B)	*Schemes of National Horticulture Board*	
6.	Development of Nutritional Garden in Rural Areas	12.50
7.	Development of bee keeping for improving productivity	18.87